बिहार सरकार

गृह विभाग

प्रतिवेदन

2009 – 2010

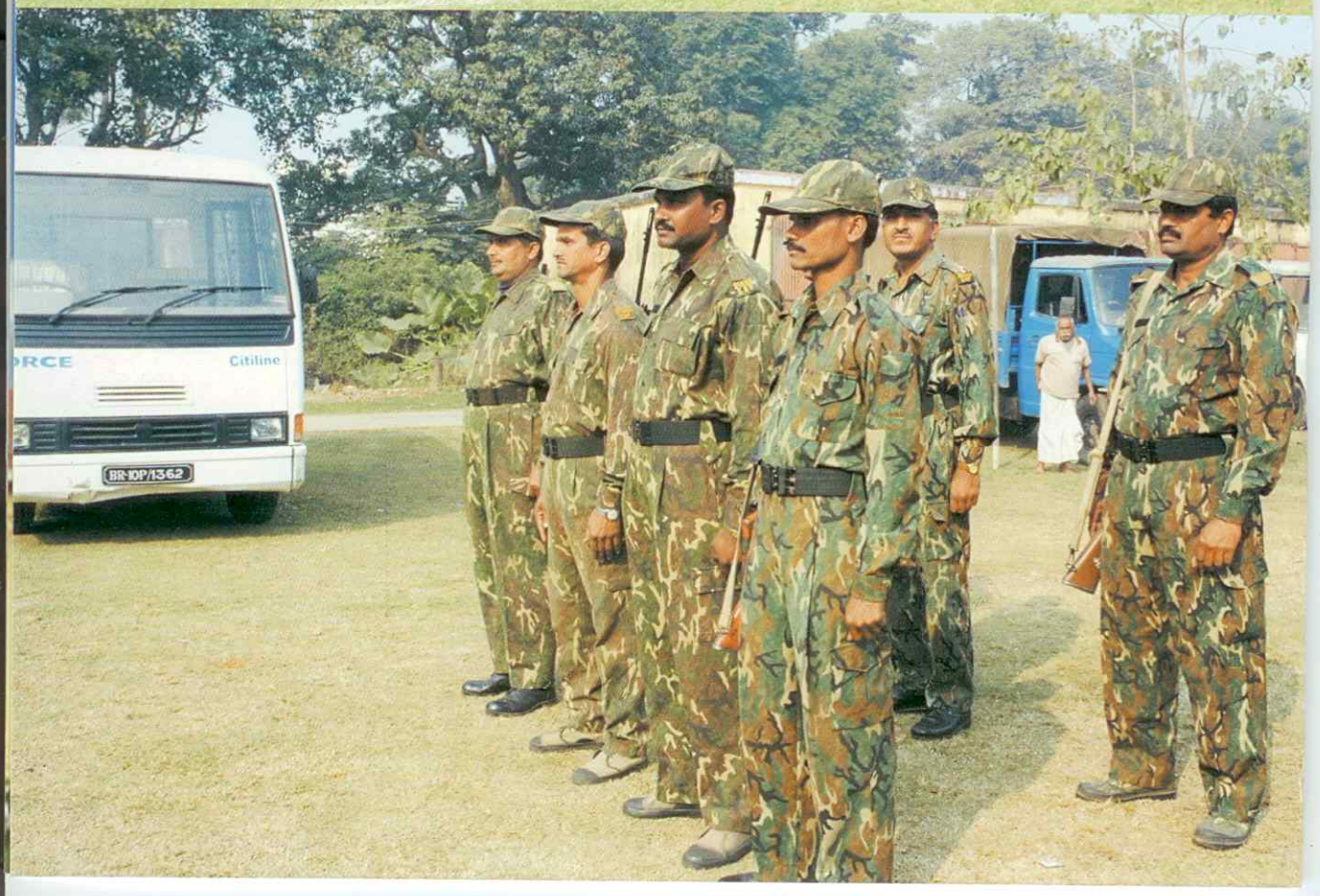
Citiline
BR-1DP/1362

गृह विभाग

पुलिस

1. राज्य में अपराध पर लगा अंकुश उत्तरोत्तर प्रभावी होता जा रहा है। अपराध के प्रमुख शीर्षों में लगातार कमी आ रही है। साम्प्रदायिक एंव जातीय तनाव मुक्त समाज की परिकल्पना आज धरातल पर है। जनता सपरिवार अपने घरों से निकलकर आवश्यकतानुसार अपना कार्य कर रही हैं। राज्य के नागरिक भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चाहे दुर्दान्त अपराधकर्मी हो या नए अपराध करनेवाले, सबके विरूद्ध बिना भेद–भाव के तथा सख्ती से कारवाई हो रही है।
2. राज्य में प्रतिवेदित अपराधों के ऑकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि न तो काण्डों को दबाया जा रहा है न ही अनुसंधान में किसी प्रकार पक्षपात का भाव प्रदर्शित किया जा रहा है।

Bihar Crime Figures 2004 To 2009

Year	Murder	Dacoity	Robbery	Kidnaping for Ransom	Road Dacoity	Road Robbery	Bank Dacoity	Bank Robbery
2004	3861	1297	2909	411	287	1875	30	27
2005	3423	1191	2379	251	224	1310	26	8
2006	3225	967	2138	194	211	1251	15	5
2007	2963	646	1729	89	151	1109	19	9
2008	3029	640	1536	66	146	897	16	7
2009 (up to May)	1236	280	704	30	80	395	2	1

3. सरकार की प्राथमिकता थी कि फिरौती के लिए अपहरण के काण्डों पर प्रभावशाली अंकुश लगाया जाए । फलस्वरूप 2004 में जहॉ 411 काण्ड फिरौती

के लिए अपहरण के प्रतिवेदित हुए थे एवं वर्ष 2005 में 251, वहीं यह संख्या घटकर वर्ष 2006 में 194, वर्ष 2007 में 89, वर्ष 2008 में 66 तथा 2009 (मई तक) मात्र 30 मामले प्रतिवेदित हुए हैं।

4. अन्य गम्भीर अपराधों की घटनाओं में भी स्पष्ट रूप से कमी हुई है । जहाँ वर्ष 2004 में 3861 हत्या की घटनायें हुई थीं वहीं वर्ष 2005 में 3423, वर्ष 2006 में 3225, वर्ष 2007 में 2963, वर्ष 2008 में 3029 एवं 2009 (मई तक) मात्र 1236 घटनाएँ हुई हैं। डकैती की घटनायें वर्ष 2004 में 1297, वर्ष 2005 में 1191, वर्ष 2006 में 967, वर्ष 2007 में 646, वर्ष 2008 में 640 एवं 2009 (मई तक) 280 हुई है। लूट की घटनायें वर्ष 2004 में 2909, वर्ष 2005 में 2379 से घटकर वर्ष 2006 में 2138, 2007 में 1729, वर्ष 2008 में 1536 तथा 2009 (मई तक) 704 रह गयीं हैं। सड़क डकैती की घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आई हैं । वर्ष 2004 में 287, वर्ष 2005 में 224 घटनाओं से घटकर वर्ष 2006 में 211, वर्ष 2007 में 151, 2008 में 146 एवं 2009 (मई तक) 80 घटनायें हुई हैं । सड़क लूट की घटनायें भी घटकर वर्ष 2004 में 1875, वर्ष 2005 में 1310 की अपेक्षा वर्ष 2006 में 1251, वर्ष 2007 में 1109, वर्ष 2008 में 897 एवं 2009 (मई तक) में 395 हुई हैं।
तुलनात्मक अपराधिक आकड़े इस बात का द्योतक है कि डकैती, लूट, फिरौती हेतु अपहरण इत्यादि जघन्य अपराध पर नियंत्रण रखने में प्रभावकारी कामयाबी मिली है।

5. फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में तो कमी आई ही है, अपहरण की अन्य घटनाओं में भी सुधार हुआ है । इनमें से अधिकतर घटनायें अनुसंधान के बाद असत्य सिद्ध हुईं एवं विवाह के प्रयोजन से युवतियों को भगाने की भी थीं । कई काण्ड ऐसे भी प्रतिवेदित हुए जिनमें अभिभावकों के भय से, या परीक्षा के भय से या लोभ के कारण घर से लोग भागे थे। कुछ घटनाओं में तो बरामदगी के बाद यह पता चला कि बच्चे सिनेमा एवं टेलीविजन पर प्रसारित होनेवाले संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने की लालच में घर से भागे थे ।

6. सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपराध नियंत्रण ही नहीं है बल्कि यह भी है कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के मामलों का भी विचारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय । इस पर कारगर कार्रवाई की जा रही है।

7. महिला उत्पीड़न को रोकना भी सरकार की प्राथमिकता है । मानव व्यापार को रोकने के लिए एवं महिलाओं तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग (अनैतिक पनन) को रोकने के लिए तीन एन्टी ह्यूमैन ट्रैफिकिंग इकाइयों का गठन पटना, मुजफ्फरपुर एवं